

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50 संख्या: 287

प्रभात

कोटा, गुरुवार 31 जुलाई, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:
(अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?
(ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।
(स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?
(द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला, रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

कभी इसकी पुष्टि की, और न सरकारी स्तर पर इसका खंडन किया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर ने इस भ्रम को दूर नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने दावा किया कि, “संघर्ष विराम में किसी भी विश्व नेता की भूमिका नहीं थी।”

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निदोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकीयों की पहचान, उनके मूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक और झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला उनके 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति नौगमीकम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका निष्प्रभावी नहीं होगी। अतः अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए लालू प्रसाद की आरोप तय करने में देरी की मांग खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त साहित्यिक जनरल एसबी राजू ने लालू की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर

- याचिका में यह मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, कि उक्त न्यायालय, लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र फाइनल न करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोप पत्र दायर होने से लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

करने के कारण उन पर जुर्माना लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया। यह दूसरा अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को राहत देने से इन्कार किया है। इससे पहले 18 जुलाई को भी अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी हार कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई तय की थी।
यह मामला 18 मई 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राहम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज

■ आयोग ने बीलवा स्थित सहारा सिटी के मामले में दिये गये आदेश की पालना नहीं करने के अवमानना के 56 मामलों में यह निर्णय सुनाया।

दिया। आयोग के न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह व मुकेश और सदस्य रामनिवास सारस्वत ने यह आदेश भारतीय माहना व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया। आयोग के स्थायी गिरफ्तारी वार्ंट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

ये सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं और संवैधानिक आचरण समूह (कॉन्स्टिट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप) से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने लिखा, “बिहार में मतदाता सूची के इस “निरर्थक” विशेष पुनरीक्षण को जारी रखना और इसे आगे चल कर देश भर में लागू करना, भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है।”
पत्र में कहा गया है, “हम यह पत्र गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की नींव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पर सीधा हमला हो रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “यह हमला बेहद चालाकी से किया जा रहा है, जहां

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हैं। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।”

पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिये दस्तावेजों की जांच के मामले में उदार और लचीला रवैया अपनाया था, आयोग अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश भारतीयों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिये पूर्ण दस्तावेज नहीं होते। उस समय यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से गरीबों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय उपायों की जरूरत होती है। अब यह प्रक्रिया पलट दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लंबे समय से चले आ

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है।
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है।

अधिकारियों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह “असाधारण स्वविवेकाधारित अधिकार” दे दिया है, जिससे मतदाता “जोड़ने या हटाने के मामलों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।”
पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

■ सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से दहते हुए, एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नवीनतम चर्चा के अनुसार, धनखड़ आंध्र के कांग्रेस नेताओं से मिलकर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आये, उन्हें एनडीए छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे मोदी सरकार अल्पमत में आकर गिर जाए

धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य गहराता ही जा रहा है!

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर की अन्नपूर्णा रसोई के बारे में राज्य सरकार के 16 जून के आदेश पर रोक लगाई।

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। हालांकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार से जुड़े स्रोतों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, क्योंकि वे कांग्रेस नेताओं के साथ गुप्तचुप गलजोल बढ़ा रहे थे और सरकार गिराने की साजिश में लगे थे। स्रोतों के अनुसार, इसके लिए धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं की एक बैठक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के साथ आयोजित कराने की कोशिश की थी, ताकि वे एनडीए से अलग हो जाएं और संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ जाए। हालांकि कहा जाता है कि नायडू ने

- चंद्रबाबू नायडू ने इस “साजिश” से प्र.मंत्री मोदी को अवगत कराया और धनखड़ से इस्तीफा लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ चाहते थे कि न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” का प्रस्ताव, राज्यसभा में पारित हो, जिससे वे “इम्पीचमेंट” की कार्यवाही के लिए अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व एक वरिष्ठ जुरिस्ट का चयन खुद करते।
- पर, लोकसभा द्वारा 145 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहले पारित हो गया।

इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ की योजना की जानकारी दे दी। धनखड़ संदेह के घेरे में थे, क्योंकि

उनका विभिन्न राजनीतिक दलों से नाता रहा है। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनूं से जनता दल के सांसद रहे और 1990-91 में संसदीय

कार्य राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद 1991 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जाईन कर ली और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। फिर 1993 से 1998 तक वे किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उन्होंने 2003 में भाजपा जाईन की और पार्टी की कानूनी समिति का नेतृत्व किया।
21 जुलाई को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से कथित साजिश के प्रयासों पर सवाल किया। धनखड़ ने नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू से शिकायत की थी कि संसद भवन से लगे उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है और कुछ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

■ सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।
बुनियादी ढांचे की कमी से दहते हुए, एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बहकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थान में स्कूल भवनों का ढहना- “आओ फूलों के जनाजे देखो”

आपने हमने जनाजो पर फूल चढ़ाते हुए तो बहुत देखे हैं, मगर खुद फूलों के जनाजे देखे तो दिल दहल गया। सात बच्चे जर्जर स्कूल की क्लास रूम में दब कर मर गये और कोई हल्ला ना हुआ। सन्नाटा पसरा रहा है चारों ओर। उनके लिए ना कोई अगरबत्तियाँ जलाई गईं ना ही कोई जुलूस निकाल गये। वे बच्चे गरीब थे इसलिये सरकार ने उनकी हैसियत देख कर उनकी जान की कीमत दस लाख लगाई गई। शिक्षा मंत्री घूम आये, दोषी को सजा देने का आश्वासन देकर। इतना बड़ा हादसा और कोई इस्तीफा नहीं, कोई दोषी नहीं। संवेदनशै्र मर चुकी हैं, हम स्त्रार्थी हो चले हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिये था मगर ये सम्भव नहीं था क्योंकि मृतकों में हमारा कोई नहीं था।

छोटे-छोटे मासूम बच्चों का जब सामूहिक संस्कार हुआ तो मोक्ष धाम की धरती भी कांप गई। अधिकांश सरकारी स्कूल कांपती स्थिति में है। एक सर्वे में 90% सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब इन स्कूलों में उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे जो यहाँ पढ़ा कर सरकारी शिक्षक बने बैठे हैं। सात बच्चों की दर्दनाक मृत्यु से मन बहुत विचलित और असह्य है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। 28 जुलाई 2025 को जैसलमेर के हावूर (पूनमनगर) में राजकीय बालिका उच्च माध्यामिक विद्यालय के मुख्य द्वार का पत्थर गिरने से छुट्टी के समय एक मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, और एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह खंभा पहले से ही जर्जर हालत में था, और इसकी मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा स्थानीय सत्ता रूढ़ पाटी के विधायक छोट्टीसिंह भाटी के पैतृक गांव में हुआ है जो सरकार की उदासीनता को और भी शर्मनाक बनाता है। इससे ठीक एक दिन पहले, 27 जुलाई 2025 को जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। सीभाग्य से, उस समय कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि राजस्थान के स्कूलों की स्थिति कितनी भयावह है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पीपलटोई गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 अन्य के घायल होने की दिल दहला देने वाली घटना ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख ही दिया है। यह हादसा सुबह 7:45 बजे हुआ, जब बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की इमारत 78 साल पुरानी थी, और स्थानीय लोगों ने कई बार उसकी जर्जर हालत की शिकायत की थी। बच्चों ने हादसे से पहले छत से कंकड़ गिरने की बात शिक्षकों को बताई थी, लेकिन शिक्षकों ने इसे नजरअंजित कर बच्चों को डांटकर चुप करा दिया। इस हादसे में मरने वाले आठ बच्चे 8 से 11 साल की उम्र के थे, और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर घृष्ठ में पड़ी हैं। झालावाड़ हादसे के ठीक एक दिन बाद, नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में खरियावास के सरकारी प्राथमिक स्कूल की छत अचानक ढह गई। सीभाग्य से, इस समय कोई बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि स्कूल भवनों की जर्जरता पूरे राज्य में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि अगर बच्चे मौजूद होते, तो तौन जिम्मेदार होता? राज्य के शिक्षामंत्री मदन दिवाकर ने हादसे का नैतिक दायित्व लेते हुए कहा कि सरकार को प्रक्रिया से ही भवनों के मरम्मत का पैसा भेजना जाएगा। इसमें किसी को पैराराज नहीं हो सकता लेकिन हम हादसों का इन्तजार क्यों करते हैं। सरकार को यह सब समय से पहले क्यों नहीं सुझता। राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2023 में बीकानेर जिले के एक सरकारी स्कूल में छत का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। स्कूल की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2022 में उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की, लेकिन दो साल बाद भी वह स्कूल जर्जर हालत में है। 2021 में जयपुर के एक सरकारी स्कूल में बारिश के कारण छत से पानी रिसने की वजह से दीवार ढह गई थी, जिसमें एक शिक्षक और एक बच्चा घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट का वादा किया था, लेकिन यह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने हर बार जांच कमेटियाँ गठित कीं, मुआवजे की घोषणाएं कीं, और बच्चों की मरम्मत को नजरअंजित करने का दावा किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश वादे हवा-हवाई साबित हुए। 2023 में बीकानेर हादसे के बाद स्वीकृत राशि का केवल 30% ही उपयोग हुआ, और बाकी राशि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ गई। उदयपुर हादसे के बाद घोषित 50 लाख रुपये का उपयोग आज तक नहीं हुआ, और वह स्कूल आज भी बच्चों के लिए खतरा बन रहा हुआ है।

इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। शिक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2,710 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, और 2,256 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि समस्या व्यापक और गंभीर है, हकीकत में यह आंकड़ा भी कागजी है वास्तविकता इससे अधिक खराब है। फिर भी, सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। झालावाड़ हादसे में यह सामने आया कि स्कूल की इमारत को जर्जर भवनों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। यह न केवल लापरवाही है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। अगर शिक्षा विभाग को इस स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं थी, तो उनकी सूची कितनी विश्वसनीय है? क्या अन्य स्कूल, जो इस सूची में नहीं हैं, वाकई सुरक्षित हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर ने झालावाड़ हादसे की 'कोरेस का पाप' बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अगर पिछले पांच वर्षों में कोरेस की सरकार थी तो उससे पहले भाजपा की सरकार रही थी अत: यह बयान न केवल अनुचित है, बल्कि उस मानसिकता को दर्शाता है जो समस्याओं के समाधान के बजाय राजनैतिक दोषारोपण को प्राथमिकता देती है। क्या सात बच्चों की मौत और जैसलमेर में एक मासूम छात्रा की जान जाने के बाद भी सरकार का 'चरणबद्ध' भवनों की मरम्मत का दृष्टिकोण उचित है?

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है।

है? क्या मासूमों की जान को कीमत इतनी सस्ती है कि सरकार भवनों धीरे-धीरे ठीक करने की बात करे? जैसलमेर हादसे में, जहां सरकार के अपने विधायक के अपने गांव में ही हादसा हुआ, सरकार की चुप्पी और भी अखरने वाली है। पिछले साल स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और इस साल यह राशि बढ़ाकर 175 करोड़ रुपये की गई। लेकिन यह राशि भी अक्षर्या है, क्योंकि 2,710 स्कूलों की मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो अभी भी वित्त विभाग में मंजूरी के लिए अटक पड़ी है। यह प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार का एक जीवन्त उदाहरण है, जो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है।

झालावाड़ हादसे के बाद पांच शिक्षकों और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि बच्चों की शिकायतों को नजरअंजित करना और उन्हें डांटकर चुप कराना शिक्षकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी। लेकिन क्या यह हादसा केवल शिक्षकों की गलती का नतीजा था? शिक्षकों ने कई बार स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों से मरम्मत की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। शिक्षकों को निलंबित करना एक आसान रास्ता है, जो सरकार को अपनी जवाबदेही से बचने का मौका देता है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं, न ही उनके पास स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट या अधिकार हैं। फिर उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है? शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? जैसलमेर और जोधपुर हादसों में भी यही पैटर्न देखने को मिला, जहां सरकार ने तुरंत शिक्षकों पर कार्रवाई की, लेकिन असल जिम्मेदारी-प्रशासन और PWD-को छुने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह साफ है कि सरकार शिक्षकों को बलि का बकरा बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हां अगर यही हादसा किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाता तो पूरा प्रशासनिक अमला स्कूल संचालक के खिलाफ सक्रिय हो जाता और अब तक उसे सलाखों के पीछे धकेल चुका होता और ताबडतोड़ अदालतों और उपदेशों की बाढ़ आ जाती।

राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम हैं। एक जगह शिक्षा कहा गया है कि “जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार” भारत की कटु सच्चाई है। झालावाड़ हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी राज्यों को स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता भर साबित होगी, अगर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिवारों ने 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक पुरस्कार को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई है। जैसलमेर हादसे में भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन क्या यह मुआवजा उन मासूमों की जान वापस ला सकता है? एक पिता, छोट्टलाल, ने अपने दोनों बच्चों-कान्हा और मीना-को झालावाड़ हादसे में खो दिया। एक आठ साल का बच्चा, कार्तिक, अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। अब उसकी बहनें किसे राखी बांधेंगी? जैसलमेर में मृत छात्रा के परिवार का दर्द भी कम नहीं है। ये बच्चे गरीब और बहुजन समाज से थे, जो निजी स्कूलों की मोटी फीस नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल उनकी एकमात्र उम्मीद थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस उम्मीद को भी धोखा दिया। जैसलमेर में यह तथ्य और भी दुखद है कि हादसा विधायक के अपने गांव में हुआ, फिर भी सरकार और प्रशासन खामोश रहे।

यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हैं, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, और उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूल खराब हालत में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संकट है, जिसे नजरअंदाज करना अब असंभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की। यह कदम सराहनीय है, लेकिन यहां खानापूर्ति होकर न रह जाए? जैसलमेर और जोधपुर, झालावाड़ के हादसों के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या कार्रवाई नहीं देखी गई। पहले भी ऐसी कमेटियाँ बनती रही हैं, और नतीजा शून्य रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल भवनों की स्थिति पर स्वयं संत्रांन लेकर नोटिस जारी किया है उधर केंद्र सरकार ने भी देश भर के स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो 2021 के सुरक्षा दिशा-निर्देशों और 2016 के आवादा प्रबंधन निर्देशों के अनुसार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों का पालन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ऑडिट को गंभीरता



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदला



फेफड़ों की अत्याधुनिक देखभाल, अब उदयपुर में पहली बार...



बेसिक और एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी

एवं उदयपुर में सर्वप्रथम थोरेकोस्कोपी सूट अब PMCH में

अब फेफड़ों से सम्बंधित उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा अहमदाबाद

पल्मोनोलॉजिस्ट्स की अनुभवी टीम



डॉ. सी.एस. पुरोहित
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ



डॉ. सुनील कुमार
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी एवं क्रायो प्रोसीजर
~~₹50000~~
निःशुल्क

एडवांस्ड थोरेकोस्कोपी
~~₹50000~~
निःशुल्क



डॉ. अतुल लुहाडिया

इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एवं चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

निःशुल्क परामर्श व जाँच

निःशुल्क भर्ती

निःशुल्क चेस्ट CT-Scan & सीटी गाइडेड लंग्स बायोप्सी

निःशुल्क X-Ray, 2D Echo

निःशुल्क ब्रोंकोस्कोपी, ICDT प्रोसीजर

निःशुल्क स्पाइरोमेट्री, DLCO

उपलब्ध सुविधाएं

बेसिक ब्रोंकोस्कोपी सेवाएं

- ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज (BAL)
- बायोप्सी
- ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन (TBNA)
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी (TBLB)

- इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकें
- स्पेशल नेगेटिव प्रेशर सूट (Negative Pressure Suite)
- 24x7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू सुविधा
- एचडी वीडियो ब्रोंकोस्कोप एवं थोरेकोस्कोप उपकरण

थोरेकोस्कोपी सेवाएं

- डायग्नोस्टिक एवं थैरेप्यूटिक
- बायोप्सी • प्ल्यूरोडेसिस
- एड्हीसियोलाइसिस

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उपचार

- पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी • ब्रोंकोस्कोपी इन आईसीयू
- रिजिड ब्रोंकोस्कोपी • इलेक्ट्रोकोटर
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग क्रायोबायोप्सी (TBLC)
- क्रायो प्रक्रियाएं (क्रायो बायोप्सी, क्रायो एक्सट्रैक्शन)
- एपीसी (Argon Plasma Coagulation)
- ट्यूमर मास डिबल्किंग - वायुमार्ग से बड़ी गांठें हटाना
- फॉरेन बॉडी रिमूवल - श्वास नली में फंसी वस्तु निकालना
- भारी खून बहाव (Massive Hemoptysis) का प्रबंधन
- ग्लू थेरेपी - वायुमार्ग की ब्लीडिंग रोकने हेतु



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना



राजस्थान स्वास्थ्य सेवा योजना



कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC



जननी सुरक्षा योजना JSY

योजनाओं एवं सभी इश्योरेंस एवं TPA के कैंसलस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

अंबेरी पुलिया से पेसिफिक हॉस्पिटल बेदला के लिए आने एवं जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क वाहन की सुविधा

*नियम व शर्तें लागू

पंजीकृत मरीज इस सुविधा का लाभ 31 अक्टूबर 2025 तक उठा सकते हैं



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल

भीलों का बेदला, एन.एच.-27, प्रतापपुरा, अम्बेरी, उदयपुर - 313011 (राजस्थान)

फोन : 8690541110, 8239278607

हाड़ौती में भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद, मध्यप्रदेश से संपर्क कटा

बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत, सड़क पर आया मगरमच्छ

कोटा, (निसं)। हाड़ौती संभाग में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बीते 40 घंटे से बारिश हो रही है। इसके चलते जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद हैं। वहीं मध्यप्रदेश से संपर्क कट गया।

हाड़ौती की बड़ी नदियों के साथ-साथ उनके सहायक नदियों में भी उफान आ गया है। ऐसे में करीब एक दर्जन से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा गांव की खाड़ी (नाले) भी काफी उफान पर है, जिससे हादसे होने की आशंका है। इन नालों ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। इनके तेज बहाव में पुलिया भी टूटकर बह गई, जिन्हें मिलकर हाड़ौती में 50 से ज्यादा रास्ते बंद हैं। बूंदी में लाखेरी के नजदीक कोटा-दीसा-लालसोट मेगा हाईवे पर मेज नदी की पुलिया पर खतरा बना हुआ है। पुलिया को फिलहाल बंद कर दिया है। इस रूट के ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। हाड़ौती में कालीसिंध, परवन, पार्वती, चंबल, अरू, पाटली, नांगली, ताकली, उजाड़, सुखनी, छापी, अंधेरी, रेणुका, कूल, बाणगांग, चंबली, आहू व मेज नदी सहित अन्य सहायक नदियां भी उफान पर हैं। साथ ही नाहरगढ़ एरिया पहले से ही मध्यप्रदेश से आ रहे पानी के चलते



सड़क पर आए मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा।

डूब में तब्दील हो रहा है। बारं जिले के छबड़ा की टॉवर कॉलोनी में भी पानी प्रवेश कर गया। बारं जिले के छबड़ा में भारी बारिश के चलते गूलन में किले की दीवार के पत्थर ढह गए। इसी तरह से केलवाड़ा के जैसवा के गांव में एक घर की छत गिर गई, हालांकि घर में सो रहे पांच सदस्य तुरंत बाहर चले गए थे। इसके अलावा कोटा के खातोली इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खातोली कस्बे में बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली करना शुरू कर दिया है। लगातार पार्वती नदी में पानी की आवक हो रही है। साथ ही प्रशासन मुनादी भी कर रहा है।

थानाधिकारी मंशीराम बिश्नोई ने

बताया कि लगातार पानी की आवक होने से एहतियात बरत रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार अरुण सिंह सहित प्रशासन ग्रामीणों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करवा रहे हैं और सतर्कता बरतने के लिए कह रहे हैं। पीपल्दा क्षेत्र में मदनपुरा, गोवर्धनपुरा, संग्रामपुरा, रघुनाथपुरा, डोली, नारायणपुरा, किरपुरिया, ख्यावदा, कर्जलिया सहित कई गांव टापू बन गए हैं।

कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में एक कच्चे घर की दीवार ढहने से 79 वर्षीय खेमराज मौणा की मौत हो गई है। जबकि उनका मूकबधिर बेटा धनराज मलबा गिरने से घायल हो गया। सुल्तानपुर पंचायत समिति के सारोला पंचायत का कचनावाड़ा गांव

में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। शमशान में टीनशेड नहीं था ऐसे में तिरपाल की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। चंबल नदी की झरेल की पुलिया पर पानी 22 जून से ही यह रास्ता बंद है। जिसे सवा महीने के आसपास हो गया है। इससे कोटा जिले के खातोली एरिया का सीधा संपर्क सवाई माधोपुर से टूटा हुआ है। वर्तमान में चंबल नदी की इस पुलिया पर पानी है। यहां पर स्थित झरेल के बालाजी का मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। मध्यप्रदेश सरकार ने खातोली के नजदीक पार्वती नदी पर पुल बनाया था। यह

सबमर्सिबल पुल था जो इस बार बारिश में डूब गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार का बनाया पुल भी अक्सर डूब जाया करता था। इस बार नया बना हुआ पुल जिस पर से इस साल ही ट्रैफिक शुरू हुआ था वह भी डूब गया है। इसके चलते मध्यप्रदेश का खातोली से संपर्क टूट गया है। कोटा जिले के अयाना के नजदीक पार्वती नदी की सुरताक क्वांजापुर की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते कोटा का मध्यप्रदेश के बड़ौदा श्योपुर से संपर्क कट गया है। यह सड़क मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग बारं जिले के लोग मध्यप्रदेश के श्योपुर जाने के लिए करते हैं।

बूंदी जिले के लाखेरी के नजदीक मेज नदी की पापड़ी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है। इसे देखने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद इस पुलिया पर से आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। बारं जिले में 14 रास्ते बंद हैं। कोटा जिले में सुकेत से जुल्मी रोड, देवली मांझी से ढोटी, नौनेरा से नारायणपुरा, गैता से कीरपुरा, चेचट से चंद्रपुरा रोड भी बंद है।

सड़क पर आया मगरमच्छ:- शहर के बजरंग नगर में नहर के नजदीक एच 9 फीट लंबा मगरमच्छ देर रात को पहुंच गया था। वन विभाग को भी इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट विभाग के वॉरेंट सिंह हाड़ा ने बताया कि वह मंगलवार देर रात करीब 1 बजे पहुंच गए थे। लेकिन भारी बारिश हो रही थी। इसके चलते रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। इसके बाद उसे पौने तीन बजे रेस्क्यू किया गया। इसे ले जाकर वॉटर फिल्टर प्लांट शिवपुरा के नजदीक चंबल नदी में छोड़ा है। यह मगरमच्छ 9 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी था।

कोटा के खातोली इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराना शुरू किया

के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद इस पुलिया पर से आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। बारं जिले में 14 रास्ते बंद हैं। कोटा जिले में सुकेत से जुल्मी रोड, देवली मांझी से ढोटी, नौनेरा से नारायणपुरा, गैता से कीरपुरा, चेचट से चंद्रपुरा रोड भी बंद है।

सड़क पर आया मगरमच्छ:- शहर के बजरंग नगर में नहर के नजदीक एच 9 फीट लंबा मगरमच्छ देर रात को पहुंच गया था। वन विभाग को भी इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट विभाग के वॉरेंट सिंह हाड़ा ने बताया कि वह मंगलवार देर रात करीब 1 बजे पहुंच गए थे। लेकिन भारी बारिश हो रही थी। इसके चलते रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। इसके बाद उसे पौने तीन बजे रेस्क्यू किया गया। इसे ले जाकर वॉटर फिल्टर प्लांट शिवपुरा के नजदीक चंबल नदी में छोड़ा है। यह मगरमच्छ 9 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी था।

सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात



एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू किया।

सवाई माधोपुर, (निसं)। जिले में लगातार हो रही मूसलधार वर्षा और जल स्रोतों के उफान के बीच बुधवार प्रातः एसडीआरएफ कमांडेंट राजेन्द्र सिंह मिसौनिया के निदेशन में एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जान बचाई।

प्रातः 5:10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर भरतपुर की सी कम्पनी खण्डार थाना क्षेत्र में तैनात टीम सी-7 को मईकलां गांव में चम्बल नदी के तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया। वहीं हैडकॉस्टेबल अशोक कुमार के नेतृत्व में 10 जवानों की टीम आपदा राहत उपकरणों एवं मोटर बोट के साथ मौके पर पहुंची। क्षेत्र में कोटा बैराज के गेट खोलने के कारण नदी उफान पर थी और गांव में पानी भर गया था। रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते

■ चम्बल नदी व लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को बचाया
■ ग्रामीणों के साथ 40 मवेशियों को लटिया नदी व लटिया नाले में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

हुए 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 4 बच्चों सहित कुल 9 नागरिकों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित निकाला और नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके साथ ही ग्रामीणों के 40 मवेशियों को भी बहाव से सुरक्षित बाहर लाया गया। इसी प्रकार दूसरी ओर सवाई माधोपुर शहर के समीप लटिया नाले के तेज बहाव में फंसे 7 नागरिकों को भी एसडीआरएफ की सी-08 टीम ने प्रातः पांच बजे सूचना मिलने के बाद प्रातः 5:50 बजे तक पहुंचकर

सफलतापूर्वक बचाया। यह टीम रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में तैनात थी और इसका नेतृत्व हैडकॉस्टेबल धारा सिंह कर रहे थे। लटिया नाले का मिर्जा मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला क्षेत्रों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका था, जिससे कुछ खाना जलमग्न हो गए। रेस्क्यू टीम ने रफिसयॉ एल, जसपुर के मदद से बाइग्रस्त मकानों तक पहुंच बनाई और सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी ओर मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने बाइग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और स्थानीय निवासियों से संवाद कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने लटिया नाले के उफान से शहर के रैगर मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, प्रजापत मोहल्ला, खटीक मोहल्ला व अन्य कॉलोनियों में हुई जलभराव की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	
ई-निविदा सूचना	
दिनांक :- 30/07/2025	
निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
F-9(141)/CC/2022-2025-13 Dated 25.07.2025 UBN No. MML2526GLOBO00071	कनकात मातापुरा सिन्हाट्ट मांस गांव-मातापुरा तहसील-जयल नागौर में एक 11 / 43 की म्यूटल श्रावडिंग रेजिस्टर (एनजीआर) की आपूर्ति, स्वामता, कमीशनिंग और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य)। अनुमानित मूल्य (₹) 10.40 लाख, घरेलू राशि (₹) - 20,800/-, निविदा राशि- 1180/- अहस्ताक्षरणीय जी.एस.टी. सहित। ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए 500/- का डी.डी. जो कि एन.डी., आर.आर.एस.एल., जसपुर के नाम देय हो।
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com अथवा www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (सांख्यिकी-अनुकूल) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें। राज.सं.सं.डी/सी/25/7178	

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर	
क्रमांक :- सेवा./सं.डी./2025-26/10881	
दिनांक :- 28/07/2025	
ऑनलाइन निविदा सूचना सं. 11/2025-26	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय का आदेश से भरतपुर विकास प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में ए तथा एच श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ईप्रोक्वोरमेंट प्रक्रिया से कुल 04 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।	
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in पर http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।	
निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्नों का संशोधन http://eproc.raajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवकाश प्रदान करें।	
UBN विवरण :- 01 WAQ2526WS	

संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद (भाईजी) पंचतत्व में विलीन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद के निधन पर शोक व्यक्त किया

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं पाथेय कण पत्रिका के संरक्षक माणकचंद (भाई जी) का बुधवार को एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे एवं विगत एक माह से किडनी की बीमारी का इलाज ले रहे थे। बुधवार शाम को

- राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया।

हुए प्रचारक जीवन की कठिन साधना की। माणकचंद का जन्म 2 नवम्बर 1942 को नागौर जिले के कसारी-बड़ा गांव में हुआ था। 1966 में वे पूर्णकालिक प्रचारक बने और छह दशक तक राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर संगठनात्मक, बौद्धिक एवं वैचारिक कार्य में संलग्न रहे। वे पाथेय कण पत्रिका के प्रबंध संपादक के रूप में 34 वर्षों तक सक्रिय रहे। उन्होंने 1989 से पाथेय कण में प्रबंध संपादक की भूमिका निभाई और वैचारिक पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनके संपादकीय नेतृत्व में यह पत्रिका भारतीय विचारधारा की मुखर और प्रतिष्ठित आवाज बनी।

आपातकाल के कालखंड में उन्होंने जेल यात्रा भी की और वैचारिक प्रतिबद्धता से कभी

विवर्जित नहीं हुए। संघ के प्रति उनका समर्पण, अनुशासन, संयम, सादगी और संतुलित दृष्टिकोण ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। पाथेय कण के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया, जो दीर्घकाल तक स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने स्व. माणकचंद के व्यक्तित्व को याद

कर कहा कि उनका जीवन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए समर्पित था। समाज में राष्ट्रीय चेतना और मूल्यों के प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव याद किया जाएगा।

पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर देवनानी ने गहरा शोक व्यक्त किया। देवनानी ने माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। माणकचंद के निधन का समाचार सुने ही देवनानी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। देवनानी ने अस्पताल में माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

रुडी का राजनीतिक अनुभव बनाम बालियान की क्षेत्रीय पकड़

जयपुर/नई दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव (प्रशासन) पद के लिए होने वाला आगामी चुनाव राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच है। एक ओर है श्री राजीव प्रताप रूडी जो सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्लब की कार्यकारी व्यवस्था में दो दशकों से सक्रिय नेतृत्वकर्ता, जिनकी प्रशासनिक दक्षता और समावेशी दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया है।

दूसरी ओर है श्री संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री,

- भाजपा के दो नेता आमने सामने, रुडी को मिल रहा सर्वदलिय समर्थन
- फ्रेंडली मुकाबले की आड़ में तीखी टक्कर, क्लब चुनाव बना चर्चा का केंद्र

जो क्षेत्रीय सांसदों और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समर्थन से मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष सरकार से समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने इसे फ्रेंडली मुकाबले के रूप में सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया है।हाल ही में संसद में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर रात्रिकालीन चर्चा के दौरान

एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। बताया जाता है कि जब सदन में सांसद मौजूद थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए श्री रूडी से पूछा कि इतनी रात को भी वोट मांग रहे हैं? और फिर स्वाभाविक जिज्ञासा से यह भी पूछा कि कैसा चल रहा है? राजनीतिक हलकों में इस प्रसंग को अधोषिप्त समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि मानव तस्करी एक गंभीर विषय है और सरकार ने इसे रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

शर्मा बुधवार को पुलिस मुख्यालय में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों की सुरक्षा विषय पर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में भी मानव तस्करी एवं महिला तथा बाल सुरक्षा विषय के महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं।

‘युवाओं में लोकतंत्र की बेहतर समझ बढ़ाने की पहल’

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शनिवार को राजस्थान विधान सभा में प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय युवा संसद होगी। युवा संसद में जयपुर शहर के विद्यालयों के विद्यार्थी, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुये राजस्थान विधानसभा के सदन में संसदीय प्रक्रियाओं पर वाद-विवाद करेंगे। देवनानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी राष्ट्र की दिशा तय करने वाली शक्ति है। उन्हें यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया की सही समझ मिले, तो वे समाज के सजग प्रहरी बन सकते हैं। युवा संसद इसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे छात्र-छात्राएँ केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर समाज और व्यवस्था को गहराई से समझ सकें।



दिन भर बारिश का दौर जारी रहा कभी तेज तो कभी फुहार। सावन के महीने में बारिश की झड़ी लगी रहने से सूरज भी नहीं निकला। सहर के लगभग सभी इलाके में सड़के दरिया बन गई , रेलवे स्टेसन अंडर पास व खाशा कोठी पर भरा बारिश का पानी।

1936 विद्यालयों में मरम्मत के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर। झालावाड़ के पीपलोट स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। उन्होंने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी दिन शाम को साढ़े 6 बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

मेवात, डंग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के

- हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया

लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रैस्पोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम बस एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें नेतृत्व सबसे अभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अथॉरिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में हैं और वह है, आमजन के साथ तादात्म्य कर उनकी आंकाक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकांक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करें।

मुंबई साइबर क्राइम के नाम पर 80 लाख की ठगी



सोवन मंडल

जयपुर। साइबर ठगों ने अपनी शांति चालों से अजमेर की बयासी वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और डिजिटल ऑरेंट का डर दिखाकर उनसे अस्सी लाख की भारी भरकम राशि ऐंट ली। इस हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मुख्य खाताधारक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बैंक खाते में ठगी की गई सारी रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि यह

घटना 23 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच हुई। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए महिला से संपर्क साधा और खुद को मुंबई साइबर क्राइम का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला को डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का झांसा दिया और कानून की कार्रवाई से बचने के नाम पर उनसे अस्सी लाख अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

प्रकरण अजमेर में दर्ज होने के बाद इसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राजस्थान, जयपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके बाद जांच में तेजी आई। साइबर थाने की विशेष टीम ने ठगी गई राशि के लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। जांच में पाया गया कि ठगी की गई पूरी अस्सी लाख की राशि एक ही बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह खाता सोवन मंडल पुत्र संतोष (30) निवासी धूलिया हावड़ा पश्चिम बंगाल का था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सोवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उससे आगे की पूछताछ जारी है।

पांच सदस्यीय कमेटी डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में करेगी संशोधन



केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत(बांये) ने डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैठक ली।

- बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए

अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ, जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठ

मुख्यमंत्री ने वर्षा पीड़ित जयपुर शहर की स्थिति का निरीक्षण किया

उन्होंने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक बनने वाली एलीवेटेड रोड की प्रगति जानी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी-टू बाईपास, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर रूक कर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों व ड्रेनेज सिस्टम की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग छह घण्टे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों एवं ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड के पास ब्रथ्सवेली नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई तथा नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया और बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया।

के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्तों के लोगों एवं बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी तथा आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी चौराहे पर

पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्कल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने महाराजा सूरजमल सर्किल व केसर नगर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए।

शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने चौरडिया पेट्रोल पंप तिराहे पर रुककर सांगानेर थाने से चौरडिया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक बनने

वाली एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर चाय भी पी।

इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

विपक्ष का मानना है, दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और वर्तमान स्थिति पर भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे सरकार की तैयारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख सवालों के जवाब देने में असफल रही, जैसे आतंकवादी पहलुगाम में घुसे कैसे और हमले के बाद कहीं चले गए? क्या वे मारे गए, या अब भी फरार हैं?

विपक्ष ने सरकार द्वारा तीन आतंकियों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने पूछा कि भारत ने कितने लड़ाकू विमान इस संघर्ष में खोए? ट्रम्प की कथित मध्यस्थता के बाद नमाला रोकने से भारत को क्या राजनीतिक लाभ मिला? इसके अलावा, विपक्ष ने इस संकट के दौरान चीन और

पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी पर भी स्पष्टता की मांग की। इसके बावजूद, सरकार ने इस महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पहलू को नज़रअंदाज़ किया, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक समन्वय के कई संकेत मौजूद थे।

कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की भूमिका ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की आक्रामक बयानबाज़ी, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक स्थिरता से मेल नहीं खा रही। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जनता को सुरक्षा से जुड़ी समुचित जानकारी नहीं दी गई। यह एक ऐसी चूक है, जो न केवल जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है।

अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया

वॉशिंगटन, 30 जुलाई। लंबे समय से जारी अनिश्चितता पर विराम लगाते हुये, अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी और रूस से सैन्य उपकरण तथा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रथ सोशल पर लिखा कि भारतीय उत्पादों पर पहली अगस्त से 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जायेगा। उन्होंने भारत को "मित्र" बताते हुये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से दोनों देशों के बीच कारोबार कम रहा है। इसका कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है, जो दुनिया में सर्वाधिक आयात शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत में गैर-मौद्रिक बाधायें भी सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत भारी मात्रा में

■ ट्रंप ने कहा कि भारत -अमेरिका में कारोबार कम होने का कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है।

रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। ऐसे समय में, जब सभी चाहते हैं कि रूस "यूक्रेन में हथ्थारें" रोक दे, भारत चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीददार है। उन्होंने लिखा कि उसका रूस से ऐसा व्यापार करना गलत है और घोषणा की कि पहली अगस्त से भारत 25 फीसदी आयात शुल्क भरेगा। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की एवज में जुर्माना भी भरेगा। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में भारत पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकलपीठ ने ये आदेश प्रकरण में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि वे चार सप्ताह में इस सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करें। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि शहर की सड़कों की वर्तमान हालात और उन्हें सुधारने की स्थिति क्या है। इसके साथ ही अदालत ने जलभराव और उफानते सीवर की समस्या के लिए उठाए गए कदमों व रोड निर्माण में अमानक सामग्री व तकनीक अपनाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों व बिना जांच इनके बिल पास करने वाले लोगों के नाम भी बताने को कहा है। अदालत ने मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारता आरज़ु माथुर, अधिकारता तनवीर अहमद, संदीप

पाठक और मधुसूदन सिंह राजपुरोहित को भी नियुक्त किया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मानसून में शहर की सड़कों के हालात बदतर हो रहे हैं, जिससे उसकी विश्वव्यापी इमेज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

हर मानसून में यहाँ जलभराव, बाढ़ और जल निकासी की समस्या होती है। जल निकासी की समस्या से रोजमर्रा के जीवन तथा पर्यावरण के साथ-साथ, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी समस्या निदान करने में असफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि निर्माण में अमानक सामग्री व तकनीक अपनाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों व बिना जांच इनके बिल पास करने वाले लोगों के नाम भी बताने को कहा है। अदालत ने मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारता आरज़ु माथुर, अधिकारता तनवीर अहमद, संदीप

धनखड़ के इस्तीफे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अपॉइंटमेंट्स को रोक जा रहा है। उसी दिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू गैरहाजिर रहे। उसी के बाद अचानक इस्तीफे की खबर आई। धनखड़ के आवास पर रखे गए विजिर्स रजिस्टर में यह दर्ज है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, महासचिव जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की अक्सर मेजबानी की। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आगह किया, तब नड्डा से कहा गया कि वे धनखड़ को सावधान करें। उन्हें यह भी बता दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में महाभियोग के जरिए नहीं होगी। इस बीच, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में महाभियोग के लिए 145 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास हुआ। धनखड़ उस समय तक 50 सांसदों के न्यूनतम हस्ताक्षर भी नहीं जुटा पाए थे, जो राज्यसभा में प्रस्ताव

लाने के लिए जरूरी थे। इसलिए घोषणा की गई कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपा गया है, और वे ही आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह भी बताया गया कि राज्यसभा में अब तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा के 145 सांसदों का प्रस्ताव ही मान्य होगा। हालांकि, लोकसभा में न्यूनतम 100 हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं। इस घटनाक्रम के साथ ही, धनखड़ की वह योजना विफल हो गई, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् की नियुक्ति अपनी पसंद से करना चाहते थे।

अब यह अधिकार स्वमेव लोकसभा अध्यक्ष को चला गया है। सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि वह यह दिखाता चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर वह खुद सख्त है और वो ही यह प्रस्ताव लाई है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के भरोसे पर टिका हुआ नहीं होता है। यह अपना आंतरिक मूल्य रखता है और दुनिया में कहीं भी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक इनके बिल पास करने वाले लोगों हैं। मगर आरबीआई की आक्रामक रणनीति इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले खतरों को गंभीरता से ले रहा है: जैसे कि अस्थिर अमेरिकी डॉलर, व्यापार युद्ध, बढ़ती महंगाई, और भू-राजनीतिक तनाव।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की फिर से टैरिफ लगाने की धमकी हालिया वैश्विक चिंता की एक वजह बनी है। उनके बयानों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और डॉलर की प्रधानता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षा कवच के साथ-साथ, स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन जाता है। यह कदम वैश्विक दृष्टानों में भी मेल खाता है। ब्रिक्स देश, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लंबे समय से डॉलर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सोना, जो कि एक सार्वभौमिक मूल्य का भंडार रहा

है, उनकी योजना में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। भारत के लिए यह केवल बैंकें शीट में ज्विधता लाने का कदम नहीं, बल्कि एक तरह की "रिज़र्व डेमोक्रेसी" भी हो सकती है। इसके घरेलू कारण भी हैं। भारतीय रुपया भले बिकत हो, फिर भी तुलनात्मक रूप से स्थिर हो, फिर भी तेज कीमतों में उछाल या अचानक पूंजी निकासी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में अधिक सोना रखकर आरबीआई अपने लिए सुरक्षा आधार तैयार करता है, एक ऐसी संपत्ति, जो ब्याज दरों, प्रतिबंधों या मुद्रा गिरावट से प्रभावित नहीं होती।

आलोचक यह कह सकते हैं कि सोना ब्याज अर्जित नहीं करता, जबकि सरकारी बॉन्ड ब्याज देते हैं। मगर जब दुनिया आर्थिक संकट में हो, तो स्थिरता, मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के कदम यह दिखाते हैं कि वह तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक स्थायित्व पर ध्यान दे रहा है। असल में, यह सोना-खरीद अभियान केवल सतर्कता नहीं है, बल्कि यह डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था में एक मौन अविरास का

ऑपरेशन सिंदूर केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है- नड्डा

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी।

उन्होंने कहा कि देश में फौज और पुलिस तो वही होती है लेकिन सरकार के काम करने का तरीका उस